[Shri Thimmaiah]

see that the outlook of the people changes and people do not observe untouchability. But, unfortunately, the machinery that is there in the Community Development areas never bothers about the propagation of untouchability. They deliver some speeches here and there and call some people and say: "You do not observe untouchability; you behave well and so on." If we go to the same area, however civilised a Scheduled Caste person may be, he will not get a cup of water. If he goes to a mofussil place, he will never be allowed to enter a hotel.

How does it happen in these areas? There is a machinery there and we are spending a lot of money on them. There are so many village level workers and officers and others. It will be sufficient if untouchability is removed in at least Community Development areas and NES blocks. Land alone cannot solve the economic problem.

They have got their heriditary industries. They know tanning and shoe-making and many other things. They are experts in making leather goods. In the Community Development areas, these village level workers can collect statistics about these people who are cobblers and know the work of shoe-making and collect them and bring them under co-operative societies and give them some aid and give some raw materials and advance so that they can earn more money through the improvement of their cottage industries. That is not being done today. I say that whatever facilities are there in the Community Development areas, they are meant for the caste Hindus and not for the Scheduled Caste people. I dare say that it has not directly helped these people in any way. That is, apart from any scheme that is strictly meant for these people, it has not helped them.

Mr. Deputy-Speaker: Is he trying to finish within another minute?

Shri Thimmaiah: I will finish it. (*Interruptions.*) I shall resume my seat.

Mr. Deputy-Speaker: He promised to finish within a minute but he has suddenly sat down. All right.

An Hon. Member: That was before he saw the time.

Mr. Deputy-Speaker: There is a paper to be laid on the Table of the House.

PAPER LAID ON THE TABLE

REPORT OF THE COMMISSIONER FOR SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES ON HIS VISIT TO RIOT AFFECTED AREAS OF RAMANATHAPURAM DISTRICT OF MADRAS

Shri Datar: Sir, I beg to lay on the Table a copy of the Report of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes on his visit to the riot affected areas of Ramanathapuram District of Madras, as directed by the Speaker. [*Placed in Library. See* No. LT-454/57.]

Shri Sonavane: Is it corrected?

Mr. Deputy-Speaker: That will be studied and then it will be known. We go to the next business.

EDUCATION MINISTERS CONFERENCE

श्री स० म० बनर्जी (कानपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, आपको याद होगा कि २१ नवम्बर, १९५७ को एक सवाल माननीय शिक्षा मंत्री जी के सामने आया था और उस सवाल में चन्द एक चीजें पूछी गई थीं। हमारे दिल्ली शहर में १९ और २० सितम्बर को स्टेट मिनिस्टर्स आफ एजुकेशन की जो कान्फ्रेंस हुई थी, उसके बारे में पूछा गया था

कि उसमें क्या फैसले किये गये थे । उस सवाल में जो मुख्य चीज पूछी गई थी वह यह थी कि :

"(i) introduction of universal free and compulsory education for children upto the age of eleven;

(ii) constitution of a smaller joint body of the representatives of the Union and State Governments in place of the Central Advisory Board of Education.

(iii) nationalisation of text-books; and

(iv) sanction of grants directly to Hindi organisations of a national character for propagation of Hindi in non-Hindi speaking areas;"

इसके उत्तर में एक स्टेटमेंट सभा की मेज पर माननीय मंत्री जी ने रखी थी । लेकिन उस स्टेटमेंट को पढने से माननीय सदस्यो को इत्मीनान नही हुआ और उन्होने कुछ सवालात मंत्री महोदय से पूछे । इस के बाद अध्यक्ष महोदय ने यह तजवीज पेश की कि इसके लिये आधे घंटे का डिसकशन हो ।

मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान कुछ चीजो की ओर आकर्षित करना चाहता हू । मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो यह कास्टीट्यूशनल डायरेक्टिव था कि छः से चौदह साल के बच्चो को फ्री तालीम दी जाये उसको बदल दिया गया है और छः से ग्यारह साल के बच्चों को फ्री तालीम देने के सिद्धान्त को मान लिया गया है । इस उम्र को कम कर देने के बावजूद भी जो प्रोग्रेस है, जो प्रगति है वह स्लो है । शिक्षा प्रणाली तथा शिक्षा पद्धति आज भी त्रुटिपूर्ण है । उन बच्चों की शिक्षा का जो प्रबन्ध है, वह आज भी सन्तोषजनक नहीं है । इस वास्ते मैं माननीय मंत्री जी से पूछूंगा कि इस स्कीम के अन्तर्गत आज कितने हमारे बच्चे हैं जो तालीम पा रहे हैं तथा कितने प्रान्तों में हम यह तालीम दे रहे हैं । माननीय मंत्री जी ने एक सवाल के उत्तर मे कहा था कि जो सेंट्रली एडमिनिस्टर्ड एरियाज हैं, उनमें हम लागू करने की कोशिश करेंगे । दिल्ली शहर में भी मैं यह पूछना चाहता हूं कि इस स्कीम को कहां तक हम लोगो ने लागू किया है ।

दूसरी चीज जो आज हमारे सामने है वह थ्री ईयर डिग्री कोर्स की है । माननीय मंत्री जी ने एक सवाल के जवाब में इस सदन के सदस्यो को यह बताया था कि उत्तर प्रदेश ने इस चीज को नही माना है । उन्होंने कहा कि आगरा यूनिवर्सिटी और बम्बई यूनिवर्सिटी ने अभी तक इसको स्वीकार नही किया है । मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं और मैं समझता हू कि आदर्शवादी दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो थ्री ईयर डिग्री कोर्स जो है वह एक आदर्श की चीज है और इसको हमें मान लेना चाहिये और सिद्धान्ततः इसको माना भी गया है । लेकिन उसमें इतना खर्चा है, इतने अखराजात हैं, इक्विपमेंट का इतना खर्चा है तथा जो मुश्किलात हैं जिनकी ओर प्रान्तीय सरकार ने या यूनिवर्स्टीस ने माननीय मंत्री महोदय का ध्यान खीचा है, उसको हल करने के लिये, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हू, कोई तरीका ढूढा गया है, इस खर्चे का इन्तजाम किया गया है ?

इसके बाद मैं यह भी पूछना चाहता हूं कि किस तरह से यह कहा जाता है कि शार्टेज आफ टीचर्स है । इसके बारे में भी एक आइटम एजुकेशन मिनिस्टर्स की कानफ्रेंस के एजेंडा मे थी । इस शार्टेज के बारे में कहा गया है कि मकानो की तकलीफ है । जो स्टेटमेंट इस सदन की टेबल पर रखी गई हैं उसमें कहा गया है कि मकानों की तकलीफ

[श्री स० म० बनर्जी]

की वजह से दिक्कतें पेश आ रही हैं । यहां पर यह लिखा है :—

Shortage in teaching personnel.

The possibilities of providing Housing to the teachers to attract them to the profession may be explored. Ministry of Works, Housing and Supply be asked to examine the question of incorporating the housing programme, especially for women teachers in rural areas, as a part of the housing programme of low paid employees.

यह एजेंडा था ।

मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान कुछ चीजों की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं । क्या यह बात सही है कि हमें टीचर्स जिन में मैं विमन टीचर्स को भी शामिल करता हूं, इस कारण नहीं मिल रहे हैं कि मकानों की शार्टेज है तथा उनके लिये हमें मकानात नहीं मिल रहे हैं ? मेरे ख्याल में केवल यही एक तकलीफ नहीं है । इसके अलावा और भी कई तकलीफें हैं जिनका टीचर्स को सामना करना पड़ता है । यह तकलीफ भी उन में से एक तकलीफ हो सकती है । टीचर्स और खास तौर से हमारी मातायें तथा बहनें जो देहातों में जाती हैं, उनको तकलीफ अवश्य होती है । लेकिन क्या यह बात भी सही नहीं है कि देहातों में जो मास्टर लोग जाते हैं उनकी आर्थिक दशा दिन-ब-दिन बद से बदतर होती जा रही है । अभी हाल ही में एक टीचर्स कान्फ्रेंस में जाने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ था । एक देहात के मास्टर साहब जो काफी बुजुर्ग थे, खड़े हो गये और अपनी दुःखभरी कहानी उन्होंने हम लोगों को सुनाई । उन्होंने कहा कि तनख्वाह तीन चार महीनों में एक दफा मिल जाती है । हमने पूछा कि और क्या काम आपको करना पड़ता है ? उन्होंने कहा कि सुबह दस बजे से स्कूल है लेकिन आठ बजे जाता हूं और दरवाजे दरवाजे जा कर बच्चों को पुकारता हूं । उनकी मातायें नाराज हो जाती हैं और किसी किसी जगह तो यह भी कहती हैं कि खाना तो खा लेने दो । उसने कहा कि हमारा काम तो चरवाहे का है । तमाम जगहों से बच्चों को इकट्ठा करना पड़ता है और कभी कभी तो उनको उनके घर भी पहुंचाना पड़ता है । मैं पूछना चाहता हूं कि आज के महंगाई के जमाने जब कि कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं यह जरूरी नहीं है कि न सिर्फ उनके लिये मकान का इंतिजाम किया जाये बल्कि उनकी आर्थिक दशा को सुधारने का, उनकी आर्थिक स्थिति को ऊंचा करने की ओर भी ध्यान दिया जाये । मैं पूछना चाहता हूं कि इस बारे में सरकार क्या कदम उठा रही है ?

आज अगर आप देखें तो आम तरीके से टीचर्स के बारे में कहा जाता है । एजुकेशन की पद्धति, शिक्षा की प्रणाली के बारे में तो बात है ही, लेकिन जितनी मास्टरों की शार्टेज हम महसूस करते हैं, वह क्यों है ? इसकी जीती जागती मिसाल है कि अभी दिल्ली शहर में पाक डाउन स्ट्राइक की बात हुई । उस वक्त मंत्री जी ने बयान सभा पटल पर रखा और कालिंग अटेंशन के के जवाब में कहा कि कुछ ऐसी दिक्कतें हैं, कुछ अड़चनें हैं, आडिट रिक्वायरमेंट्स हैं जिनके बारे में अड़चनें आ गई हैं, जिनको हल करने की हम कोशिश कर रहे हैं । उन टीचर्स का, अगर आप देखें, शायद १२ दिसम्बर को माननीय मंत्री जी से एक डेपुटेशन मिला था । मुझे मालूम नहीं कि अखबार की खबर कहां तक सही है, लेकिन मि० गुप्ता ने जो उसके जेनरल सेक्रेटरी हैं कहा है :—

"A deputation of teachers met Dr. Shrimali on December 12th., and he expressed his inability to help in the matter because the country was passing through a financial crisis".

यह उन्होंने जवाब दिया । मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आज अगर क्राइसिस है तो वह देश भर के लिये है और उसके रिसोर्सेज का इन्तजाम हम और आप राष्ट्रीय पैमाने पर कर रहे हैं, लेकिन टीचर्स की आज गिरती हुई हालत है । आपको मालूम है कि बंगाल में टीचर्स ने एक प्रदर्शन किया । इतने दिन के बाद यह फैसला अचानक किया गया कि वह टीचर्स यू० पी० एस० सी० की मार्फत कंफर्म किये जायेंगे । मैं पूछना चाहता हूं कि जो बंगाल के टीचर्स ने, आल बंगाल टीचर्स असोसिएशन ने, यह बात साफ तरीके से सामने रखी थी कि क्या यह सच नहीं है कि अगर हम सरकारी नौकर नहीं हैं, पब्लिक सर्वेंट नहीं हैं, तो हमें यू० पी० एस० पी० की मार्फत क्यों कंफर्म किया जाय, उसके बारे में आपने क्या किया? केरल में जो एजुकेशन बिल पास हुआ है, हो सकता है कि राष्ट्रपति उसको अपनी असेंट दे दें, और तब वहां के टीचर्स यह कह सकें कि चूंकि यू० पी० एस० सी० की बात हो सकती है तो क्यों न वह सरकारी नौकर माने जायें । लेकिन मैं यह पूछना चाहता हूं कि, जिस डिमांड के लिये उन्होंने मजाहरे किये, प्रदर्शन किये, क्या यह जायज है कि ऐसे टीचर्स से एक्स-पीरिएंस्ड टीचर्स से यह कहा जाय कि जाइये, यू० पी० एस० सी० की मार्फत आइये? अब मालूम होता है कि उस प्रदर्शन के बाद, एजिटेशन के बाद, यह फैसला किया गया कि जिसकी पांच साल की सर्विस है, जिसे पांच साल का एक्सपीरिएंस है, उसे नहीं जाना पड़ेगा । हमारे देश के निर्माता, जो कल बच्चों को बड़ा करेंगे, हमारे देश के नौनिहाल बच्चों को हर तरीके से अच्छा सिटिजेन बनाने की कोशिश करेंगे, उन टीचरों को जो अपनी तनख्वाहों के लिये, अपना जीवन धारण करने के लिये, अपनी जीविका के लिये, लाठी चार्ज और टीअरगैस, तमाम तरह की चीजें सहनी पड़ें, और उनके घर में हाहाकार मचा हो, तब हम किस तरह से कहें कि वे देश के निर्माता हैं और देश का निर्माण करेंगे । इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि अगर हो सके, और वह सही समझें, तो इस पर कुछ प्रकाश डालें कि हम उनकी गिरती हुई दशा को किस तरह से सुधारने जा रहे हैं ।

हमारे सामने चौथी चीज टेक्स्ट बुक की है । नशनलाइजेशन आफ टेक्स्टबुक्स का मैं स्वागत करता हूं । राष्ट्रीयकरण होना चाहिये । लेकिन एक चीज राष्ट्रीय-करण के बारे में भी है । कुछ जगहों पर मैंने देखा, मेरी उम्र तो ज्यादा नहीं है, लेकिन मैं कहूंगा कि मैंने स्कूल में जो तालीम पाई वह अपने बड़े भाइयों की किताबों से ही पाई । मुझे मालूम है एक के० पी० बासू का अल्जबरा था । हम तीन भाइयों ने उसी से पढ़ा । एक हाल्स ऐंड स्टेवेंसन की जामेट्री हुआ करती थी, उसी से हम चार भाइयों ने पढ़ा । एक उर्दू की मुरक्का ए अदब उर्दू हुआ करती थी, हमारे पूरे खानदान ने उसे पढ़ा । लेकिन आज आप देखिये कि एक अजीब हालत है । मुसीबत तो यह है कि हर साल किताबें बदल जाती हैं । मुझे मालूम नहीं कि अगर आप इस एजुकेशन को इतनी एक्स्पेंसिव बनायेंगे तो इस एक्स्पेंसिव एजुकेशन में किस तरह से हमारे गरीब बच्चे तालीम याफ्ता हो सकेंगे । जब यह बात ऐसी है तो संजीदगी के साथ आप सोचें आप पेरेंट्स की शक्ल में, पिता की शक्ल में सोचें जो कि अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता है । हम लोग चाहते हैं कि बच्चा पढ़े, लेकिन दरअस्ल जब वह किताबों की फेहरिस्त लाता है तो हम ढूंढते रहते हैं कि किसी जगह से पुरानी किताबें मिल जायें, नहीं तो हम इंस्टालमेंट्स में खरीदते हैं । बच्चे को हम सिखाते हैं कि दूसरों की किताबों से पढ़ लो क्योंकि आखिर-कार हम किताबें खरीद तो नहीं सकते हैं । हम समझते हैं कि हम बच्चों की तरक्की कर रहे हैं, लेकिन उसकी जेहनियत गिरती रहती है, वह दूसरी तरफ तरक्की करता रहता है । ऐसी हालत में हम जिस तरीके से बच्चे को ले जाना चाहते हैं, वह होता नहीं है । इसलिये

[श्री स० म० बनर्जी]

मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि वह इस बारे में भी प्रकाश डालें तो बहतर होगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : जितना समय माननीय सदस्य लेना चाहते हैं, उतना तो आप को मंत्री महोदय को भी देना चाहिये ।

श्री स० म० बनर्जी : मैं दो मिनट में खत्म करता हूं ।

फिर यह १४ साल की बात है । ६ से १४ साल तक या ११ साल तक की एजुकेशन के बारे में मैं ने आप से कहा लेकिन एक चीज उस में मैं माननीय मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हू । वह यह है कि १४ साल की कई हमारी बहनें हैं, भाई हैं, बच्चे और बच्चियां हैं, इस के बारे में उन को क्या सहूलियत दी जायेगी ? प्रेपरेटरी टु हायर कोर्स में उन के लिये क्या स्कोप है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे देश के नौजवान १६ साल की उम्र में नौकरी में चले जायें और किसी दफ्तर में पियन हो जायें या अनस्किल्ड लेबर बन जायें, भले ही ऐसे लोगों के दिलों में शिक्षा की आकांक्षा हो लेकिन उन को जाना पड़े । आप को देखना है कि देश में स्कोप हो जिस को देख कर वह आगे पढ़ सके । इस लिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन चीजों पर ध्यान कर के प्रकाश डालें । इस में काफी चीजें थी, लेकिन मौका नहीं है और मैं यह नहीं चाहता कि मैं अपने और माननीय मंत्री के बीच में, या माननीय सदस्यों के बीच मैं ज्यादा देर खड़ा रहूं । लेकिन मैं यह जरूर चाहता हूं कि कम से कम इन चीजों पर प्रकाश डाला जाय और टीचर्स की गिरती हुई हालत को, चाहे वह बहनें हों, भाई हो, माता हों या पिता हों जो भी टीचर की शक्ल में हो अच्छा किया जाय ताकि हमारा देश उन्नति कर सके और हमारे बच्चों का वाकई में देश के निर्माता की शक्ल में वह निर्माण कर सकें और उच्च आदर्श पर वह चल सकें ।

श्री जगदीश अवस्थी (बिल्हौर) : उपाध्यक्ष महोदय, समय ज्यादा नहीं है और मंत्री जी को जवाब भी देना है, इस लिये मैं मंत्री जी से केवल तीन प्रश्न करना चाहता हूं । एक तो यह कि आज देश में शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है । खास तौर से प्रारम्भिक शिक्षा जो हमारे देश में है, उस के सम्बन्ध में यह कठिनाई पड़ गई है कि ज्यादातर स्कूल जिला बोर्डों के हैं । जब कभी यहां पर यह प्रश्न उठाया गया तो यह कहा जाता रहा कि यह प्रारम्भिक स्कूल जिला बोर्डों के अधीन हैं, राज्य सरकारों के अधीन हैं । जब उन की दशा गिरती जा रही है, तो मैं जानना चाहूंगा कि इन प्रारम्भिक स्कूलों की अवस्था को ठीक करने के लिये जो कि सब से आवश्यक चीज है, क्या उन्होंने कोई सुझाव रक्खा है और क्या कोई खास बात उन्होंने रक्खी है ।

इस के बाद जो माध्यमिक शिक्षा प्रणाली है, उस में आम तौर से यह देखा गया है कि सरकारी स्कूल और अन्य माध्यमिक स्कूल जो एक साथ चलते हैं, उन के अध्यापकों के वेतन अलग अलग होते हैं । कुछ माध्यमिक स्कूल इतने अच्छे हो गए हैं कि उन की स्टैन्डिंग बहुत अच्छी हो गई है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री इस पर विचार कर रहे हैं कि जितने ऐसे स्कूल हैं, जिन की स्टैन्डिंग २० वर्ष की हो चुकी है उन का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाय ताकि उन के अध्यापकों के वेतनों की अच्छी सुरक्षा हो सके और उन को सिक्योरिटी आफ सर्विस हो सके ?

तीसरा सवाल . . . . .

उपाध्यक्ष महोदय : बहुत से सवाल तो नहीं हो सकते हैं ।

श्री जगदीश अवस्थी : तीसरा सवाल जो मुझे मंत्री जी से करना है वह यह है कि आज जो देश के अन्दर निरक्षरता की

समस्या है उसको हल करने के लिये क्या वह इस प्रकार की योजना पर विचार कर सकते हैं कि एक साक्षरता सेना का निर्माण किया जाये ताकि देश भर में जो ९३ प्रतिशत जनता निरक्षर है उसको साक्षर बनाया जा सके ताकि लोगों का बौद्धिक स्तर ऊंचा हो सके और वे हमारी लोकतंत्री मान्यताओं को समझ सकें और यह जान सकें कि आज देश और सरकार के सामने क्या क्या समस्यायें हैं। यह निरक्षरता की बुराई देश में खाद्य समस्या की तरह फैली हुई है। इसको किस तरह से दूर करने का विचार किया जा रहा है।

एक प्रश्न मैं और पूछना चाहूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : कई सवाल मिल कर तो एक स्पीच बन गयी।

श्री जगदीश अवस्थी : आज जो अहिन्दी भाषा भाषी क्षेत्र हैं उनमें सबसे बड़ी समस्या हिन्दी प्रसार की है। माननीय मंत्री जी ने और शिक्षा मंत्रालय ने हिन्दी प्रसार के लिये कौन कौन ठोस कार्य किये हैं और उनका क्या नतीजा आया है यह मैं जानना चाहूंगा।

Shri Vasudevan Nair (Thiruvella): I would like to ask one question. I would like to know whether Government has taken any decision in the question of giving aid to those colleges which are run directly by the State because those colleges are not helped by the University Grants Commission.

Shri Keshava (Bangalore City): May I ask one very small question?

Mr. Deputy-Speaker: According to the rules he is not entitled, nor was the member from the left, because no previous intimation had been given. Now that another member has asked a question, the hon. Member may also put one question.

Shri Keshava: Has the Government any scheme for transforming the present schools into basic schools?

The Minister of State in the Ministry of Education and Scientific Research (Dr. K. L. Shrimali): I am very glad that hon. Members have raised some of these questions. It gives me an opportunity to explain to the House some of the decisions which were taken at the Education Ministers' Conference.

The most important item which the Conference considered was with regard to compulsory education for the age group to 14. The House has already approved the Second Five Year Plan and the estimates and the targets of the Second Five Year Plan for the age group 6 to 11 and 11 to 14.

At present the position with regard to the age group 6 to 11 for the whole country is that about 51 per cent. of the school-going children are attending educational institutions. The Plan had laid a target to raise this number to 62.7 per cent. Then, with regard to age group 11 to 14, the present estimates are, that is, 1955-56 estimates, that 19.2 per cent. of children are in the educational institutions and the Plan had laid down 22·5 per cent. as target for the age group 11 to 14.

The Plan was discussed in this House and it gave its approval. It was realized even at the time when the Plan was considered that it was not possible to realise....

Shri Sinhasan Singh (Gorakhpur): Are they all India figures?

Dr. K. L. Shrimali: Yes, all India figures. It was realised even at that time when the Plan was discussed that the directive laid down in the Constitution cannot be fulfilled. This is not a very happy thing and I can assure the House that I am as sorry as any of the members here because democracy cannot function effectively unless we can fulfil this directive of the Constitution as quickly as possible.

[Dr. K. L. Shrimali]

But, at the same time, we cannot be completely unaware of our resources. We have examined all the possibilities and it was found that the country does not have adequate resources to fulfil the directive. This is a very unpleasant and, at the same time, hard reality with which, I am afraid we have to reconcile ourselves. The country must produce more wealth in order that we might be able to make education free and compulsory, as quickly as possible and fulfil the directives of the Constitution, which we have laid before us.

Shri Dasappa (Bangalore): We should provide more for education?

Dr. K. L. Shrimali: If there are interruptions, it will not be possible for me to cover the subject in time.

Mr. Deputy-Speaker: There should be no questions and no statements.

Shri Dasappa: No income without education.

Dr. K. L. Shrimali: Recently, a panel of the Planning Commission went into this question, approached this question in a realistic manner and they suggested that by the end of the Third Five Year Plan, we might provide free and compulsory education for all children between the ages 6 to 11. As far as ages group 11 to 14 is concerned, it is very difficult to say when that target may be realised. It may take 10 years or 20 years or even more. It all depends on the availability of resources. But it is quite clear that the targets that were laid down in the directive that was given in the Constitution cannot be fulfilled, not because the Government are not keen to implement it, but because the Government do not have adequate resources to fulfil that directive.

The Education Ministers' Conference approached this problem in a realistic manner and gave general approval to the recommendation which was made by the panel of the Planning Commission; that is, attempt should be made to provide free and compulsory education to all children between the age 6 and 11 in course of time, provide free and compulsory education for children between the ages 11 and 14 and it is difficult to fix any time limit with regard to the age group 11 to 14.

The second question that was raised was with regard to university education. This question with regard to the provision of a three year degree course has now been discussed by various learned bodies and Commissions for several years. For nearly 40 years this question is being debated in the country. The University Education Commission presided over by Dr. Radhakrishnan made the same recommendation. The Mudaliar Commission also made the same recommendation. Government are now trying to implement the recommendation which was made by these two Commissions

Again, here, it is a question of finding suitable resources. The Government of India appointed a Committee under the Chairmanship of Shri Deshmukh to go into this question. Shri Deshmukh has submitted the report and he has suggested that it is possible to implement the recommendations with regard to the three year degree course.

The hon. Member asked me as to the amount that would be required and whether the Government will have the resources to implement this recommendation. The Deshmukh Committee has estimated an expenditure of Rs. 15 crores for the introduction of this scheme in all the colleges in India during the Second Plan period. A sum of Rs. 5 crores is to be provided by the Ministry of Education, Rs. 2½ crores by the University Grants Commission and the balance of Rs. 7½ crores by the State Governments or by the management of colleges. That is how it is proposed to

implement this scheme of three year degree course. Again, it will depend on whether all these funds will be available. I hope that this question which is being debated in the country for such a long time will be implemented and adequate resources will be available for this purpose. The Education Ministers' Conference generally approved of the recommendation with regard to the three year degree course.

With regard to nationalisation of text books, this item was included in the agenda because the different States wanted to exchange their experiences with regard to this question. The various State representatives and State Ministers explained the practices which existed in their different States. In Punjab, it was said that these experiments have been carried out over the last few years and it is understood that they propose to create an autonomous body to undertake the production of textbooks. The Government of Andhra has recently taken a decision to nationalise textbooks, starting from the primary standards from 1957-58. The books at the secondary stage will be taken up later.

In Kerala, the process started in 1956. Part of the printing work was formerly being done by the Government Press, and part of it by private persons The Government of Kerala have now taken a decision to take over the entire work of printing the textbooks. The Government of Kerala intend organising co-operative societies in every high school and sending the required number of textbooks to these schools for distribution among the primary schools around them.

In West Bengal textbooks for classes three and four of the primary school are prepared by a board appointed by the Government. Textbooks under this system costs the student about one-third of the cost under the old system; besides, the quality and the get-up of the books has considerably improved.

In U.P. this experiment has been tried since 1948 for class five, and is being extended from class to class. In Rajasthan also, textbooks have been nationalised up to class five.

So, Members will see that the extent of nationalisation has varied from State to State.

We were told in Bihar 160 books have been nationalised, while Assam has produced only three books. On the whole, U.P., Bihar, Kerala, Punjab, Madhya Pradesh, Bhopal, Vindhya Pradesh and Jammu and Kashmir have nationalised textbooks on a fairly large scale.

In Bombay the State Government was not very enthusiastic with regard to nationalisation of textbooks, because they said they had a different experience.

The general concensus of opinion with regard to nationalisation of textbooks was that if it is tried under proper conditions, it will be in the interests of both the pupils and the parents, as better quality books could be made available at cheap rates. No firm decision was taken by the conference with regard to this. This item was included mainly because the ministers wanted to exchange their experiences, and, as I have said, the experience of most of the State Governments was that nationalisation of textbooks has produced better results.

Another question which the hon. Member had raised was with regard to the economic conditions of teachers. I am in full agreement with the hon. Member that the economic conditions of teachers in this country and most of the countries is bad, and no reforms in education are possible unless we increase the salaries of teachers.

The Ministry of Education has taken some measures. I would not say they are adequate measures, but again considering our resources, I think they are measures which will go a long way in ameliorating the conditions of teachers.

[Dr. K. L. Shrimali]

We have written to the State Governments—the House will remember that Education is not a Central subject, but even then it was realised that something must be done to improve the conditions of the teachers as a whole—to increase the salaries of teachers, and we said that we were prepared to pay fifty per cent. of the increased expenditure as far as the primary school teachers were concerned

For secondary school teachers also, we said we would be prepared to pay funds on the same basis In fact, for the secondary teachers we have gone beyond this, and said that even if the State Government cannot find the matching funds, we would be prepared to release our share.

The House is already aware that the University Grants Commission is already giving grants to the universities for increasing the salaries of university teachers

So, at all levels we have made an attempt to increase the salaries of teachers As I said, I am not satisfied with the existing scale of salaries, but we have always to keep in view the resources which are available to us

On the one hand, there is a pressure for expansion of education. The pressure is irresistible The country must go forward in its programme of free and compulsory education. This programme cannot be stopped and shbuld not be stopped At the same time, we have to increase the salaries of teachers, and with the limited resources that we have at our disposal, we have to meet both these rival claims at the same time

Considering the position as it is before us, I think the Government of India has done something of which we can be proud. I am glad that most of the State Governments also have come forward to increase the salaries of the teachers, and they have taken advantage of this offer.

Shri S. M. Banerjee: May I know which of the States have increased the salaries?

Mr. Deputy-Speaker: Let these questions be answered first before fresh ones are asked.

Shri S. M. Banerjee: Then the time may be over.

Dr. K. L. Shrimali: Then, the question was raised with regard to shortage of teachers Again, this is linked up with the general economic situation. As we improve the salaries of teachers, we are bound to get more teachers, not only in quantity, but of better quality. So, this is linked up, and the Ministry of Education is already aware of this problem and is making an effort to solve it.

Another hon Member raised the question as to what we are doing with regard to nationalisation of local board schools and provincialising the institutions Some of the State Governments have already taken certain steps It is really the responsibility of the State Governments. I would say the same thing about nationalisation of schools also It is not possible for the Central Government to give a directive to the State Governments in this matter This is a matter which entirely lies within the sphere of the State Governments.

With regard to giving aid to colleges, I have already stated that if the scheme suggested by the Deshmukh Committee materialises, then we shall be able to release grants to the affiliated colleges also

Now, I come to Hindi propagation. Did the hon. Member ask me with regard to Hindi-speaking areas or non-Hindi-speaking areas?

Shri Jagdish Awasthi: About non-Hindi-speaking areas.

Dr. K. L. Shrimali: We had issued a pamphlet in regard to this subject, and that pamphlet is available in the Library. I would not take up the

time of the House by giving details, because all the steps that the Ministry has taken with regard to the translation of technical words, preparation of dictionaries, releasing of grants to the non-Hindi-speaking States for propagation of Hindi, preparation of text-books etc., are described in that pamphlet, and I shall be very glad to give more information to the hon. Member if he is interested in this subject.

The last question was whether Government have any scheme.....

Shri Jagdish Awasthi: What steps Government have taken to remove illiteracy.

Dr. K. L. Shrimali: ... for the transformation or conversion of elementary schools into basic schools. The House is already aware that the Government of India have accepted basic education as the pattern of national education, and we are giving grants to the State Governments for converting all schools into basic schools. We hope that in course of time, all the schools will be converted into basic schools, and there will be one single pattern as far as the education of the people and the masses is concerned.

I think I have covered most of the points raised by hon. Members.

Shri S. M. Banerjee: May I know.

Mr. Deputy-Speaker: Now, the House will stand adjourned and meet again at 11 A. M. tomorrow.

18.33 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday, the 19th December, 1957.